LOK SABHA

Friday, October 22, 1982/Asvina 30, 1904 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सिविलियन अध्यापकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

+

*290. श्री मंगत राम प्रेमी :
श्री शिव शरण वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविलियन अध्यापकों के वेतनमान सामान्य स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों की तुलना में बहुत कम हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार सामान्य स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों तथा इन सिविलियन अध्यापकों के वेतनमानों में समानता लाने का है और यदि हां, तो कब ;

(ग) ये वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir. No professional training in education has been prescribed for the Civilian Teachers. Accordingly, on the recommendations of the Third Pay Commission, the following scales of pay are available to them:—

(i) Rs. 260—400 (for Under-Graduate Teacher)

(ii) Rs. 330—560 (for Graduate Teacher)

On the other hand teachers in general schools are required to possess professional diploma/certificate and are placed in the scale of Rs. 330—560.

(b) to (d). In view of (a) above the question of disparity does not arise.

श्री शिव शरण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सिविलियन टीचर्स के वेतनमान सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान की अपेक्षा बहुत निम्न हैं और इनकी पदोन्नति भी समय समय पर नहीं हो पाती है, यह उनके लिये एक बड़ी विडम्बनापूर्ण बात है, क्या सरकार उनके वेतनमान में कोई सुधार लाते हुए सामान्य विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके स्केल के बराबर करने के लिए तैयार हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सिविलियन टीचर्स का वेतनमान अन्य अध्यापकों के वेतनमान के समान करने के लिए तैयार है, यदि हां, तो वह उच्च वेतनमान क्या होगा ? और उसे कब से लागू करने के लिए तैयार हैं ? इसी क्रम में मुझे यह भी कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व जो सिविलियन टीचर्स नियुक्त

किए गए थे, वे सरप्लस में करके विभिन्न मंत्रालयों में दूसरे निम्न पदों पर नियुक्त कर दिए गए हैं और उनके पूर्व के वेतनमान की अपेक्षा उन्हें निम्न वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

इस प्रकार वास्तव में तो सरकार उनके साथ जो अन्याय कर रही है, मैं इस संबंध में जानना चाहूंगा कि जिनको सरप्लस में निकाल कर दूसरे विभागों में नियुक्त किया गया है, क्या उनका वेतनमान भी नए वेतनमान के समान करने के लिए सरकार तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

SHRI K. P. SINGH DEO: As I have mentioned in the answer, there is no discrimination or disparity as far as the scale is concerned. In fact, prior to the Third Pay Commission, the Civil School Masters were getting two scales of pay *i.e.*, 130—200 for Graduates and 110—180 for non-Graduates. As a result of the recommendations of the Third Pay Commission, their scales were revised to 330—560 for graduates and 260—400 for non-graduates.

As far as surplus teachers are concerned, whatever number of teachers were found to be surplus, they were posted to alternative jobs according to their suitability and willingness. If the hon. Member has any specific instance of people getting lower pay or scale, he can bring that to our notice and we will examine that.

SHRI P. NAMGYAL: Will the Government consider to have a running grade for all the teachers as the grades of teachers in our country are very low and because of that. Government teachers try to go to other services? To prevent this, will the Government consider to have a running grade for them with qualification bar and efficiency bar so that they may not get hustrated in the service?

SHRI K. P. SINGH DEO: The education cover in the Armed Forces is provided by the help of combatant unit education instructors, who train these people. But this is a suggestion which needs examination.

श्री रामेश्वर नीखरा : क्या मंत्री महोदय को सन् 1978 में पूछे गए प्रश्न संख्या 245 की जानकारी है, जिसमें तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि जो सरप्लस टीचर घोषित किए गए हैं उनकी पे को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके बाद पार्लियामेंट मेंबर्स ने 20 प्रश्न पूछे हैं और मैंने भी करीब 15 पत्र लिखे हैं और लिस्ट भी दी है। क्या कोई कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई ? अभी अगर मैं जानकारी दूं तो क्या कार्यवाही की जाएगी ?

SHRI K. P. SINGH DEO: There has been correspondence on this. And the hon. Member did bring it to our notice we are still examining it and we shall revert back to it.

Public Distribution of Vanaspati Ghee

*293. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government propose to start public distribution of vanaspati ghee in a fixed quantity each month for meeting the consumers' requirements;

(b) the steps so far taken in this regard; and

(c) what are the details in regard to the prices of vanaspati, brand packing size, monthly quantity etc. to be drawn by the consumers from the Fair Price Shop?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI MOHAMMED USMAN ARIF): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.